Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

"हाउसिंग फॉर ऑल - सबके लिए घर,
ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है।"
– नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री

1 CRORE and more

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी

के अंतर्गत "सबके लिए आवास" के सपने को पूरा करने की दिशा में **27 दिसम्बर, 2019** एक गौरवपूर्ण दिन है। 1.12 करोड़ आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष केवल चार सालों में 1 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति प्रदान कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। यह पिछली योजनाओं में 10 सालों में स्वीकृत आवासों की तुलना में 10 गुना से ज्यादा है। स्वीकृत आवासों में से 60 लाख से ज्यादा आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है और लगभग 32 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए अपनाई गई बेहतर रणनीति व समस्याओं के शीघ्र समाधान से लाखों लोगों के जीवन में आया यह सार्थक बदलाव संभव हो पाया। कोआपरेटिव फेडेरलिज्म (Cooperative Federalism) की भावना के अंतर्गत राज्य सरकारों व शहरी स्थानीय निकायों, HUDCO, BMTPC, NHB जैसी संस्थाओं व रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े CREDAI, NAREDCO जैसे संगठनों का इस पड़ाव को पार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु प्रगति की मोनिटरिंग, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से online MPR, Geotagging व DBT के माध्यम से की जाती है।

GLOBAL HOUSING TECHNOLOGY CHALLENGE INDIA

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज – इंडिया

इतनी बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण और लाभार्थियों को शीघ्र आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जी ने आवासों के निर्माण में नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज – इंडिया (GHTC-India) के तहत मार्च 2019 में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया – 2019 (CTI-2019) एक्सपो–कम–कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2019–20 को Construction Technology Year भी घोषित किया गया। GHTC- India के तहत देश के छः राज्यों में अलग–अलग अल्टरनेट न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से 6 Light House Project का निर्माण किया जा रहा है। जो सभी stakeholders के लिए एक LIVE laboratary के रूप में कार्य करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रावधान के अलावा नेशनल अर्बन हाउसिंग फण्ड के माध्यम से एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से 60 हजार करोड़ रूपये के फण्ड की व्यवस्था की गयी है।

अंगीकार

योजना में लाभार्थियों को सभी आधारभूत सुविधाओं सहित घर के अतिरिक्त नए वातावरण के अनुरूप उन्हें सक्षम बनाने एवं बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु देशभर में "अंगीकार" अभियान चलाया जा रहा है। इसमें घर–घर जाकर लाभार्थियों को जल व उर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फिट इंडिया मूवमेंट व पोषण अभियान आदि की जानकारी दी जा रही है। साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं आयुष्मान भारत के साथ कन्वर्जेन्स किया गया है।

योजना के Credit Linked Subsidy Scheme घटक के अंतर्गत मध्यम वर्ग के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पहली बार उन्हें इसमें शामिल किया गया है। लाभार्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से एक real टाइम वेब बेस्ड पोर्टल – CLSS आवास पोर्टल (CLAP) लांच किया गया है। जिसके माध्यम से लाभार्थी ब्याज सब्सिडी हेतु दिए गए अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं।

अब बस CLAP करिए

योजना के अंतर्गत अब तक के 6 लाख करोड़ में से 3.24 लाख करोड़ रूपये के निवेश से सीमेंट, स्टील, पेंट्स, टाइल्स, ईंट उद्योग आदि को बढावा देने के साथ–साथ 0.62 cr प्रत्यक्ष व 1.26 cr अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी को इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुँचाने के सफर में राज्य / संघ राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, व लाभार्थियों का विशेष योगदान रहा जिन्होंने अपने पक्के घर के सपने को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।